DR. K. MALAISAMY: Let all these things be taken care of. Will it be effective and adequate? That is the point I would like to know.

SHRI A.K. ANTONY: We are very particular that we must take effective and adequate steps. We must redress the grievance of the *jawans.* That is why I asked the Committee that they must give the report within two months. Once I get the report, we will start implementing the report.

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत झारखंड को निधि का आबंटन

*206. **श्री अजय मारू:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत झारखंड को कितनी राशि आवंटित की गयी है;

(ख) इसमें से कितनी राशि का उपयोग हुआ है; और

(ग) झारखंड में इस योजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) झारखंड राज्य को अक्तूबर, 2006 तक नियमित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 890.00 करोड़ रु० और विश्व बैंक से सहायता प्राप्त प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 75.00 करोड़ रु० आबंटित किए गए हैं।

(ख) कार्यक्रम के अंतर्गत अक्तूबर, 2006 तक रिलीज किए गए 504.41 करोड़ रु० में से 434.26 करोड़ रु० का व्यय हुआ है।

(ग) अब तक स्वीकृत परियोजनाओं का कुल मूल्य 633.03 करोड़ रु० है। 3362.37 कि०मी० लम्बाई के 629 सड़क कार्य मंजूर किए गए हैं जिनमें से 2367 कि०मी० लम्बाई के 447 सड़क कार्य पूरे हो चुके हैं। 995 कि०मी० लम्बाई के 182 सड़क कार्य प्रगति पर हैं।

Fund under PMGSY to Jharkhand

†*206. SHRI AJAY MAROO: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the amount that has been allocated to the State of Jharkhand under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana;

(b) the amount utilized out of the said amount; and

(c) the current status of the said scheme in Jharkhand?

†Original notice of the question was received in Hindi.

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI RAGHUVANSH PRASAD SINGH): (a) Rs. 890.00 crore under regular Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana and Rs. 75.00 crore under World Bank funded PMGSY has been allocated to the State of Jharkhand upto October, 2006.

(b) An expenditure of Rs. 434.26 crore has been incurred against the release of Rs. 504.41 crores upto October, 2006 under the programme.

(c) The total value of projects sanctioned so far is Rs. 633.03 crore. 629 road works for a length of 3362.37 Kms have been sanctioned out of which 447 road works covering a length of 2367 Kms have been completed. 182 road works for a length of 995 Kms are in progress.

श्री अजय मारू: महोदय, ''प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना'' एनडीए के शासन काल में आरम्भ की गई, भारत सरकार की अति महत्वाकांक्षी चरणबद्ध योजना थी। इसके तहत भारत सरकार ने शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दे कर राज्यों के अनजुड़े आबादी समूह को हर मौसम वाली सड़कों से जोड़ने का कार्यक्रम आरम्भ किया था। इसके प्रथम चरण में एक हजार से अधिक आबादी वाले गांवों और द्वितीय चरण में 500 से अधिक आबादी वाले गांवों को जोड़ने का कार्यक्रम था।

महोदय, झारखंड एक पिछड़ा हुआ राज्य है और इस कार्यक्रम के तहत, जैसा कि मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा कि अक्तूबर, 2006 तक 890 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी। चूंकि झारखंड एक पिछड़ा हुआ राज्य है, लेकिन वहां पर इस योजना को लागू करने में काफी कमी दिखाई गई है और 890 करोड़ में से मात्र 434 करोड़ रुपये ही व्यय हुए हैं। हालांकि दूसरे राज्यों में इस योजना के फेज छः का कार्य चल रहा है, लेकिन झारखंड में फेज चार का कार्य ही चल रहा है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस योजना को और गति से आरम्भ करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं, जिससे कि जो 434 करोड़ रुपये, जो बचे हुए हैं, उनका उपयोग हो जाए और यह अन्य राज्यों की श्रेणी में आ जाए?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, झारखंड राज्य की कंज्यूमिंग कैपेसिटी कम है। हमने उन्हें बार-बार रिमाइंड करवाया है, इसके लिए उनके सैक्रेटरी के साथ बैठक एवं परामर्श किया है, उनके मंत्री के साथ भी बैठक की है कि वे अपनी कंज्यूमिंग कैपेसिटी को बढ़ाएं। पैसे की कोई कमी नहीं है। हिसाब से यह साफ जाहिर है कि उनका हिस्सा 890 करोड़ रुपये होता है, लेकिन अभी तक वे कुल 416 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाए हैं। हमने 489 करोड़ रुपये रिलीज कर दिए हैं, साथ ही हम उन पर मुस्तैद भी हैं कि वे अपनी कंज्यूमिंग कैपेसिटी बढ़ाएं और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसे स्ट्रैथन करें। अगर इंजीनियरों की कमी है, उसके लिए भी हमने कहा है कि केन्द्र हर प्रकार की सहायता करने के लिए तैयार है, लेकिन झारखंड राज्य भी अन्य राज्यों की तरह अपनी कंज्यूमिंग कैपेसिटी बढ़ा कर गांवों को सड़कों से जोड़ने की जो योजना है, उसमें आगे आए।

महोदय, यह पैसा तो राज्यों को ही खर्च करना है। श्री अर्जुन मुंडा ने आग्रह किया था कि सैंट्रल एजेंसी को खर्चा बढ़ाने के लिए नियुक्त कर दिया जाए, उसके लिए भी हमने सहमति दे दी। राज्य सरकार पर हम मुस्तैद हैं कि वह अपना खर्च बढ़ाए और गांवों-गांवों को सड़कों से जोड़ने की जो योजना है, महोदय, चूंकि वहां पर आदिवासी बहुल इलाका है। हमारा लक्ष्य जहां देश भर में भारत निर्माण में हजार की आजादी को जोड़ना है, वहां ट्राइबल इलाके में, पहाड़ी इलाके में 500 तक की आबादी को 2009 तक हमें जोड़ देना है यह है हमारा भारत निर्माण का कार्य। माननीय सदस्य कहते हैं कि एन॰डी॰ए॰ के राज में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू हुई थी। तो जब ढाई हजार करोड़ सालाना खर्चा करना था और अब हम पांच गुना अधिक 12 हजार करोड़ सालाना खर्च करने की स्थिति में हैं। इसलिए इसको और तेजी से लागू किया गया।

श्री अजय मारू: महोदय, इस सच्चाई से हम परे नहीं हट सकते कि यह एन॰डी॰ए॰ के शासनकाल में आरम्भ हुई योजना है। महोदय, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में एक महत्वपूर्ण बात है कि हर मौसम की सड़कें बनाने का कार्यक्रम था, क्योंकि केन्द्र सरकार से शतप्रतिशत राशि जाती है। माननीय मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं कि पूरे देश में यह जो राशि जा रही है क्या सड़क उस गुणवत्ता की बन रही है और क्या कोई केन्द्रीय एजेंसी उसकी जांच कर रही है?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, एकदम साफ निर्देश हैं कि गुणवत्ता में समझौते की कोई गुंजायश नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल थ्री टियर सिस्टम है। जहां राज्य सरकारें लागू कर रही हैं वहां फर्स्ट टियर, सेकंड टियर राज्य सरकार के हाथ में है। थ्री टियर में केन्द्र सरकार द्वारा नेशनल क्वालिटी मॉनिटर को भेज करके छानबीन कराई जाती है। फिर सबसे पहले देश में टेक्नीकल ऑडिट को भी हमने इंटरोड्यूज किया है ताकि क्वालिटी में कोई गड़बड़ी न हो। और कहीं से शिकायत मिलने पर तुरन्त आदमी भेजकर नेशनल क्वालिटी मॉनिटर द्वारा उसकी जांच कराई जाती है और कार्रवाई की जाती है।

श्री राशिद अल्वी: सर, मेरा सवाल भी इसी से मुताल्लिक है कि जो प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना है, वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं उनमें से एक योजना यह भी है। लेकिन देखने में यह आया है कि जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती है उसका पूरा इस्तेमाल स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है। उसकी क्वालिटी और बहुत जगह तो ऐसा होता है हमारे यहां उत्तर प्रदेश में तो सड़क ही नहीं बनती है और उत्तर प्रदेश में ...(व्यवधान)...

श्री अमर सिंह: एकदम गलत बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री शाहिद सिद्दिकी: *

श्री अमर सिंह: *

---

*Not recorded.

श्री सभापति: बैठिए, बैठिए, प्लीज टेक योर सीट। ...(व्यवधान)...

श्री राशिद अल्वी: सर, सवाल कर रहा हूं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: जल्दी करिए। ...(व्यवधान)...

श्री उदय प्रताप सिंह: *

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है। देखिए, आप बैठिए। ...(व्यवधान)... आप प्रश्न करिए। ...(व्यवधान)... वह आप छोड़िए।

श्री राशिद अल्वी: सर, मुझे सवाल तो पूछने दीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: बैठिए-बैठिए, उनको बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)... एक मिनट, आप बैठिए। ...(व्यवधान)... आप कह रहे हैं कि सड़कें बहुत बनी हैं। ...(व्यवधान)... एक मिनट, आप बैठ जाइए। रिकार्ड पर नहीं जा रहा है, रिकार्ड पर कोई नहीं जाएगा। आप कह रहे हैं कि सड़कें बहुत बनी हैं और ये कहते हैं कि सड़कें नहीं बनी हैं। मुझे फैसला नहीं करना है कि सड़कें बनी हैं या नहीं बनी हैं। ...(व्यवधान)... इसलिए गवर्नमेंट बोलेगी कि इनकी बात सही है या आपकी बात सही है, Let the Government speak.

श्री राशिद अल्वी: सर, मेरा सवाल है कि ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: सही होगी या नहीं होगी, अगर यह बात गलत है ...(व्यवधान)... अगर यह बात सही है ...(व्यवधान)... आप बैठी-बैठी मत बोलिए। ...(व्यवधान)... आप बोलने दीजिए, बोलने से पता लगेगा। ...(व्यवधान)...

श्री राशिद अल्वी: सर, मेरा सवाल है कि ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप क्वेश्चन करिए। ...(व्यवधान)... आप क्वेश्चन पूछिए। ...(व्यवधान).. बैठे-बैठे बोलने की इजाजत नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री राशिद अल्वी: सर, मेरा सवाल मंत्री जी से है और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सवाल का जवाब मंत्री जी ही देंगे, किसी और से मेरा सवाल नहीं है। ...(व्यवधान)... मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी स्टेट्स के अंदर, ऐसे प्रदेशों के अंदर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे का मिसयूज कर रहे हैं ...(व्यवधान)... सर, मैं यू॰पी॰ का नाम नहीं ले रहा हूं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप क्वेश्चन करिए। ...(व्यवधान)...

श्री राशिद अल्वी: सर, मेरा प्रश्न यह है कि ...(व्यवधान)... सर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसकी मानिटरिंग का क्या तरीका उनके पास है? ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: ठीक है, आनरेबुल मिनिस्टर साहब, आप बताइये। ...(व्यवधान)...

---

*Not recorded.

श्री राशिद अल्वी: अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट इसका गलत इस्तेमाल करती है, तो क्या इसकी सी. बी.आई. इन्क्वायरी हो सकती है? ...(व्यवधान)...

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना एक महत्वाकांक्षी और देश के लिए महत्वपूर्ण योजना है। इसमें क्वालिटी के बारे में माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था। महोदय, सड़कों की क्वालिटी की जांच-पड़ताल के लिए थ्री टियर सिस्टम है। फर्स्ट टियर और सेकेंड टियर की जांच राज्य सरकारों के द्वारा की जाती है, इसका मतलब है कि दो स्तर पर उनके नीचे के पदाधिकारी और ऊपर के पदाधिकारी, इंजीनियर छानबीन करते हैं, जांच करते हैं। उसके बाद थर्ड टियर में, हर एक सड़क की, हम यहां से भेजकर जांच करवाते हैं। हम नेशनल क्वालिटी मानिटरिंग से जांच करवाते हैं और उसमें शिकायत मिलने पर, कमी मिलने पर, कहीं पर भी, उसको बनाने में ढिलाई, मैटिरियल की खराबी या कम मैटिरियल लगा है, उसके संबंध में हम कार्यवाही करते हैं। इसीलिए देश-भर में जितनी सड़कें बन रही हैं, उनमें प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की सभी सड़कों की गुणवत्ता उत्तम है। कहीं खास स्पेसिफिक शिकायत होने पर, हम उसकी जांच करवा सकते हैं। माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं, उसके बारे में हमें उत्तर देना है। उत्तर प्रदेश अपने हिस्से की राशि खर्च करने में अभी पीछे है। ...(व्यवधान)... सभापति महोदय, कई राज्य, कम से कम 15 राज्य अपने हिस्से की राशि खर्च करने में पीछे हैं। उसके लिए हम 15 राज्यों के साथ बराबर सम्पर्क में हैं। हम मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखते हैं, हम सेक्रेटरी के साथ बैठक करके मानिटरिंग करते हैं और जो राज्य पीछे छूट गए हैं, हम चाहते हैं कि उनकी भी कंज्यूमिंग कैपेसिटी बढ़े। हमें बड़ा भारी काम करना है। सभापति महोदय, हमें भारत निर्माण करना है। ...(व्यवधान)... चार वर्षों में 48 हजार करोड़ रुपया खर्च करना है और गांवों में सारी सुविधाएं मुहैया करानी हैं, इसलिए सभी सदस्यों की ...(व्यवधान)... सभापति महोदय, माननीय सदस्यों की इसमें रूचि है और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत निर्माण कार्यक्रम सफल होकर रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्रीमती जया बच्चन: सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश के बारे में आपने बहुत जिक्र किया, मुख्य मंत्री को चिट्ठी लिखी, सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं, हम पीछे हैं, वह बात सही है। अब आप महाराष्ट्र और मुम्बई के बारे में क्या कर रहे हैं? वहां तो हमारे घर के सामने की सड़कें ठीक नहीं हैं, इतना बड़ा शहर है। ...(व्यवधान)... वहां कोई सड़क ठीक नहीं है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि आप वहां के लिए क्या कर रहे हैं? ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.